पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2023 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 17449

==

राहिल अहमद, पिता- सिराजुद्दीन अंसारी, निवासी- ईशोपुर अमरुदी बागीचा, पोस्ट आफिस और पुलिस थाना- फुलवारी, जिला- पटना, बिहार- 801505

.... याचिकाकर्त्ता

बनाम

1. प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बिहार ग्रामीण विकास समाज, बिहार सरकार, पटना।
3. जिला दंडाधिकारी, जिला- पटना, बिहार।
4. उप विकास आयुक्त, पटना, बिहार।
5. प्रखंड विकास अधिकारी, दानापुर, जिला-पटना, बिहार।

....उत्तरदाता

==

उपस्थितिः

याचिकाकर्ता के लिएः श्री आतिश कुमार, अधिवक्ता

श्री रवि रंजन मलिक, अधिवक्ता

प्रत्यर्थियों के अधिवक्ताः श्री विनय कीर्ति सिंह (सरकारी अधिवक्ता -2)

श्री राजन प्रकाश, अधिवक्ता (सरकारी अधिवक्ता -2 के सहायक परामर्शदाता)

==

पटना उच्च न्यायालय नियम—बड़ी पीठ का संदर्भ—अधिकारिता बड़ी पीठ का संदर्भ—याचिकाकर्ता ने संबंधित उत्तरदाता प्राधिकरण द्वारा पारित समाप्ति के आदेश को चुनौती दी है; और अपीलीय प्राधिकरण का आदेश, जिसके द्वारा समाप्ति का आदेश पुष्टि की गई है—याचिकाकर्ता ने विभिन्न आधारों पर उक्त आदेशों को चुनौती दी, जिसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन शामिल है—जब वर्तमान याचिका को सम्मानित एकल न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया गया, याचिकाकर्ता ने सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 7056, वर्ष 2020 में एक और सम्मानित एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.01.2021 पर निर्भरता जताई—सम्मानित एकल न्यायाधीश ने अवलोकन किया कि समाप्ति का आदेश याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित किया गया और यह स्पष्ट है कि कोई भी ऐसा आदेश, जो दुर्बलता और नागरिक परिणामों को लाए, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन के बिना नहीं दिया जा सकता—समापन का आदेश आरोप के आधार पर पारित किया गया था और इसलिए, सम्मानित एकल न्यायाधीश ने याचिका को स्वीकृत किया और समापन का आदेश रद्द कर दिया गया—सम्मानित एकल न्यायाधीश ने एक भिन्न दृष्टिकोण अपनाकर याचिका को खारिज कर दिया है और इसके बाद अब कानून का प्रश्न विभाजन पीठ को संदर्भित किया गया है—यह आवश्यक नहीं है कि न्यायिक विवेक और डेकोरम के विचारों पर जोर दिया जाए कि यदि एक सम्मानित एकल न्यायाधीश किसी मामले को सुनते समय इस विचार पर झुकाव हैं कि उच्च न्यायालय के पूर्व निर्णय, चाहे वह विभाजन पीठ के हों या एकल न्यायाधीश के, पर फिर से विचार करना आवश्यक है, तो उन्हें एकल न्यायाधीश के रूप में उस जांच में शामिल नहीं होना चाहिए, बल्कि मामले को विभाजन पीठ को संदर्भित करना चाहिए या, एक उचित मामले में, संबंधित कागजात मुख्य न्यायाधीश के सामने रखना

चाहिए ताकि वह एक बड़े पीठ का गठन कर सकें जो इस प्रश्न का परीक्षण कर सके— सम्माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा किया गया संदर्भ गलत तरीके से समझा गया है और अस्वीकार्य है और, इस कारण, वर्तमान याचिका में, याचिका को खारिज करने के बाद इसे निर्णय नहीं किया जा सकता।

(पैराग्राफ 6, 6.3, 6.11, 7.1)

एआईआर 1965 एससी 1767; (1977) 3 एससीसी 25; (1998) 5 एससीसी 637; (2000) 1 एससीसी 644 — **निर्भर किया गया।**

==

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==

गणपूर्ति: माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार पांडे

मौखिक आदेश

(द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली)

7 20-02-2025 वर्तमान याचिका विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 07.05.2024 के आदेश के अनुसार हमारे समक्ष रखी गई है, जिसके तहत विद्वान एकल न्यायाधीश ने निम्नलिखित प्रश्न को विचार के लिए बड़ी पीठ को भेजा हैः.

"क्या विभागीय कार्यवाही, विभागीय जांच और सीसीए नियम, 2005 के प्रावधानों के तहत आरोप का निर्धारण, राज्य के विशिष्ट योजना के अंतर्गत

<u>काम करने वाले संविदा/अस्थायी/दैनिक वेतन भोगी/तदर्थ कर्मचारियों के मामले में लागू है।</u>"

<u>तथ्यात्मक संदर्भ</u>:

2. वर्तमान मामले को हमारे सामने रखने के लिए संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैंः.

2.1. याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वर्तमान याचिका दायर की है, जिसमें याचिकाकर्ता ने प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा पारित दिनांक 10.12.2019 के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उत्तरदाता संख्या 3, जिला मजिस्ट्रेट, जिला-पटना, बिहार द्वारा पारित ज्ञापन संख्या 119 दिनांक 29.01.2019 में निहित सेवा समाप्ति के आदेश को बरकरार रखा गया है। याचिकाकर्ता ने यह भी प्रार्थना की है कि दिनांक 29.01.2019 के सेवा समाप्ति के आदेश को रद्द कर दिया जाए। याचिकाकर्ता ने आगे प्रार्थना की है कि प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता को पूर्ण बकाया वेतन के साथ बहाल करने का निर्देश दिया जाए।

2.2. वर्तमान याचिका विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध की गई थी और विद्वान एकल न्यायाधीश ने आदेश में संदर्भित माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर विचार करने के बाद दिनांक 07.05.2024 के आदेश द्वारा याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि, याचिका को खारिज करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश ने पैराग्राफ 16, 17 और 18 में निम्नानुसार टिप्पणी की:

16. इसलिए, याचिकाकर्ता की सेवा केन्द्रीय सरकारी सेवक नियमावली, 2005 का पालन किए बिना भी उसके नियोक्ता द्वारा समाप्त की जा सकती है।

17. ऊपर बताए गए कारणों से, मुझे तत्काल रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं मिलती है और तदनुसार इसे खारिज कर दिया जाता है।

> *18. इससे पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूँ, मैं सम्मानपूर्वक यह दर्ज करना चाहता हूँ कि मैं सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 7056/2020 में पारित समन्वय पीठ के निर्णय से असहमत हूँ, जो रिट याचिका के साथ अनुलग्नक-17 के रूप में संलग्न है। इसलिए, मेरी विनम्र राय में, इस मामले को इस प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए बड़ी पीठ को संदर्भित करने की आवश्यकता है कि **क्या विभागीय कार्यवाही, विभागीय जाँच और सी.सी.ए. नियम, 2005 के प्रावधानों के तहत आरोप का निर्धारण, राज्य के तहत विशिष्ट योजना के तहत काम करने वाले संविदा / अस्थायी / दैनिक वेतन भोगी / तदर्थ कर्मचारियों के मामले में लागू है।***

2.3. इस प्रकार, आदेश के पैराग्राफ 18 में की गई टिप्पणियों के अनुसार, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा तैयार किए गए प्रश्न को बड़ी पीठ को भेजा गया है।

2.4. इसलिए, माननीय मुख्य न्यायाधीश ने एक प्रशासनिक आदेश पारित किया, जिसके अनुसार कार्यालय ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा तैयार किए गए कानून के उपर्युक्त प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए वर्तमान याचिका को इस खंड पीठ के समक्ष रखा है।

3. हमने श्री आतिश कुमार को याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रवि रंजन मलिक और श्री विनय कीर्ति सिंह की सहायता से सुना है, जिन्हें उत्तरदाताओं की ओर से श्री राजन प्रकाश द्वारा सहायता प्रदान की गई है।

याचिकाकर्ता की ओर से निवेदन:

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने शुरुआत में प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने एक अन्य विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 13.01.2021 के आदेश पर भरोसा किया है। 2020 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या:7056 **(रागिनी कुमारी उर्फ रागिनी कुमार बनाम। बिहार राज्य और अन्य)**। यह प्रस्तुत किया जाता है कि, उक्त याचिका

में, संबंधित विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि चूंकि संबंधित उत्तरदाता प्राधिकरण ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है, इसलिए सेवा समाप्ति के आदेश को रद्द करने की आवश्यकता है।तदनुसार, उक्त मामले में, आदेश को दरकिनार कर दिया गया और संबंधित प्राधिकारी को सभी परिणामी लाभों के साथ संबंधित याचिकाकर्ता को बहाल करने का निर्देश दिया गया।

4.1. विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करेंगे कि यदि विद्वान एकल न्यायाधीश, वर्तमान मामले में, उपर्युक्त मामले में किसी अन्य विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे, तो विद्वान एकल न्यायाधीश को कानून के प्रश्न को खण्ड पीठ को संदर्भित करना चाहिए था और खण्ड पीठ द्वारा उस विधि प्रश्न पर निर्णय दिए जाने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। हालाँकि, वर्तमान मामले में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाकर याचिका को खारिज कर दिया है और उसके बाद अब कानून के प्रश्न को खंड पीठ को भेज दिया गया है।

4.2. इसलिए याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि वर्तमान संदर्भ अपने आप में मान्य नहीं है।

<u>उत्तरदाता की ओर से निवेदन</u>:

5. उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता ने भी इस पहलू पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किए गए प्रस्तुतिकरण का समर्थन किया है।

<u>परिचर्चा</u>:

6. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदनों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वर्तमान याचिका दायर की है, जिसमें याचिकाकर्ता ने संबंधित प्रतिवादी प्राधिकरण द्वारा पारित सेवा समाप्ति के आदेश और

अपीलीय प्राधिकरण के आदेश को चुनौती दी है, जिसके द्वारा सेवा समाप्ति आदेश की पुष्टि की गई है। याचिकाकर्ता ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन सहित विभिन्न आधारों पर उक्त आदेशों को चुनौती दी। रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि जब वर्तमान याचिका विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध की गई थी, तो याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने सी.डब्ल्यू.जे.सी. में एक अन्य विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 13.01.2021 के आदेश पर भरोसा किया था। संख्या 7056/2020। उक्त मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश ने पाया कि याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही बर्खास्तगी का आदेश पारित कर दिया गया था और यह अच्छी तरह से स्थापित है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन के बिना कोई भी बुरा और नागरिक परिणाम देने वाला आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। उक्त मामले में, आरोप के आधार पर बर्खास्तगी का आदेश पारित किया गया था और इसलिए विद्वान एकल न्यायाधीश ने याचिका को अनुमति दी और बर्खास्तगी के आदेश को रद्द और दरकिनार कर दिया ।

6.1. वर्तमान मामले में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने 07.05.2024 को आदेश पारित किया और विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें दर्ज कीं। इसके बाद, विद्वान एकल न्यायाधीश ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों का हवाला दिया। इसके अलावा, विद्वान एकल न्यायाधीश ने पैराग्राफ 17 में कहा है कि उक्त आदेश में बताए गए कारणों से याचिका को खारिज किया जाना आवश्यक है और तदनुसार, याचिका को खारिज कर दिया गया है। हालांकि, इसके बाद, दिनांक 07.05.2024 के आदेश के पैराग्राफ 18 में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने आगे टिप्पणी की है कि चूंकि उन्होंने सीडब्ल्यूजेसी संख्या 7056/2020 में पारित समन्वय पीठ के निर्णय से मतभेद व्यक्त किया है, जो कि रिट याचिका में अनुलग्नक-17 में संलग्न है, इसलिए प्रश्न, "*क्या विभागीय कार्यवाही, विभागीय जांच करना और सीसीए नियम, 2005 के प्रावधानों के तहत आरोप का निर्धारण, राज्य के तहत विशिष्ट योजना के तहत काम करने वाले संविदा/अस्थायी/दैनिक वेतन भोगी/तदर्थ कर्मचारियों के*

मामले में लागू है।", विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा तैयार किया गया, वर्तमान बड़ी पीठ को संदर्भित किया गया है।

6.2. इस प्रकार, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांकित 07.05.2024 आदेश के पैराग्राफ 16 से 18 में की गई उपरोक्त चर्चाओं से यह पता चलेगा कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने पहले ही दिनांकित 13.01.2021 आदेश में किसी अन्य विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण अपनाकर याचिका को खारिज कर दिया है। इसलिए, एक बार जब याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान संदर्भ की स्थिरता के बारे में तर्क दिया है, तो सबसे पहले हम वर्तमान संदर्भ की स्थिरता के संबंध में इस मुद्दे पर निर्णय लेना चाहेंगे।

6.3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **लाला श्री भगवान बनाम राम चंद** के मामले में (ऑल इंडिया रिपोर्टर 1965 सर्वोच्च न्यायालय 1767), कहा है कि के विचारों पर जोर देना शायद ही आवश्यक है। न्यायिक औचित्य और शिष्टाचार के लिए यह आवश्यक है कि यदि किसी मामले की सुनवाई करने वाला कोई विद्वान एकल न्यायाधीश यह विचार रखने के लिए इच्छुक है कि उच्च न्यायालय के पहले के फैसलों, चाहे वह खंड पीठ के हों या एकल न्यायाधीश के, पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, तो उसे एकल न्यायाधीश के रूप में उस जांच को शुरू नहीं करना चाहिए, बल्कि मामले को खंड पीठ को भेजना चाहिए या किसी उचित मामले में, संबंधित कागजात मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखना चाहिए ताकि वह प्रश्न की जांच करने के लिए एक बड़ी पीठ का गठन कर सके।इस तरह के मामलों से निपटने का यह उचित और पारंपरिक तरीका है और यह न्यायिक शिष्टाचार और औचित्य के स्वस्थ सिद्धांतों पर आधारित है।

6.4. (1977) 3 सर्वोच्च न्यायालय के मुकदमे 25 में रिपोर्ट किए गए **एकनाथ शंकरराव मुक्कावर बनाम महाराष्ट्र राज्य** के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा 25 में निम्नलिखित टिप्पणी की हैः.

> "***25.*** *अपील के निपटारे में विद्वान एकल न्यायाधीश (जी० एन ० वैद्य,जे.) द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में एक परेशान करने वाली विशेषता की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया जाता है।विद्वान न्यायाधीश ने उसी न्यायालय के एक अन्य एकल न्यायाधीश (जे. एम. गांधी, जे.) के निर्णय को नजरअंदाज कर दिया, जिन्होंने पहले इसी तरह के मामले में निर्णय दिया था कि राज्य द्वारा अपील दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 377 (1) के तहत सक्षम नहीं थी। यह सच है कि विशेष अनुमति द्वारा अपील में इस न्यायालय के समक्ष निर्णय लंबित है।हालाँकि, यह के लिए पर्याप्त कारण नहीं हो सकता है। न्यायाधीश इसे नजरअंदाज करें और देखें कि "इस मामले को तब तक पीछे रखना अनावश्यक है जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय मामले का फैसला नहीं कर लेता।"जब एक समन्वित अदालत का निर्णय होता था, तो विद्वान न्यायाधीश के लिए इससे अलग होना खुला होता था, लेकिन उस मामले में एकमात्र न्यायिक विकल्प यह था कि वह इसे एक बड़ी पीठ को भेजे और विपरीत दृष्टिकोण अपनाकर अपील का निपटारा न करे।न्यायिक अनुशासन के साथ-साथ शिष्टाचार को यह सुझाव देना चाहिए कि यह एकमात्र पाठ्यक्रम है।"*

6.5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए उपर्युक्त अवलोकन से, यह कहा जा सकता है कि जब समन्वय पीठ का कोई निर्णय था, तो विद्वान न्यायाधीश के लिए इससे अलग होना खुला था, लेकिन उस मामले में, उनके लिए उपलब्ध एकमात्र न्यायिक विकल्प

था कि वे इसे बड़ी पीठ को भेजें और विपरीत दृष्टिकोण अपनाकर अपील का निपटारा न करें। न्यायिक अनुशासन के साथ-साथ शिष्टाचार का सुझाव होगा कि यह एकमात्र पाठ्यक्रम है।

6.6. **त्रिपुरा राज्य बनाम त्रिपुरा बार** के मामले में, **(1998) 5 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट 637** में प्रतिवेदित, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 4 में निम्नानुसार टिप्पणी की है :

> *"**4.** हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ, जिसने विवादित निर्णय दिया है, वह समन्वय पीठ दुर्गादास पुरकायस्थ [(1988) 1 गौ एल. आर. 6] के मामले में उच्च न्यायालय की पूर्ववर्ती खंड पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण नहीं ले सकती थी।यदि बाद की पीठ पहले की पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण रखना चाहती, तो उनके लिए उचित तरीका यह होता कि वे मामले को एक बड़ी पीठ को भेज देते।हमने मामले को एक बड़ी पीठ को नहीं भेजने के लिए विद्वान न्यायाधीशों द्वारा दिए गए कारणों पर विचार किया है।हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि उक्त कारणों ने मामले का फैसला करने और इसे बड़ी पीठ को नहीं भेजने को उचित ठहराया।इन परिस्थितियों में, हम उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को बरकरार रखने में असमर्थ हैं क्योंकि यह रिट याचिका में उत्तरदाता के रूप में शामिल न्यायिक अधिकारियों की अंतर वरिष्ठता के मामले से संबंधित है।उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को, जहाँ तक यह उत्तरदाता न्यायिक अधिकारियों की वरिष्ठता के मामले से संबंधित है, दरकिनार कर दिया जाता है।अपीलों का निपटान तदनुसार किया जाता है।कोई लागत नहीं।"*

6.7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई उपर्युक्त टिप्पणी से यह स्पष्ट है कि यदि बाद की पीठ पहले की पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण रखना चाहती, तो उनके लिए उचित मार्ग यह होता कि वे मामले को एक बड़ी पीठ को भेज देते।

6.8. उक्त मामले में, खंड पीठ ने मामले को एक बड़ी पीठ को नहीं भेजा और इसलिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित उच्च न्यायालय की दूसरी खंड पीठ द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप किया।

6.9. **उप-निरीक्षक रूपलाल बनाम उपराज्यपाल** के मामले में, **(2000) 1 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट 644 में प्रतिवेदित,** माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 12 में निम्नानुसार टिप्पणी की है:

> *"**12.** सबसे पहले, जिस तरह से न्यायाधिकरण की एक समन्वय पीठ ने उसी न्यायाधिकरण की एक अन्य समन्वय पीठ के पहले के फैसले को खारिज कर दिया है, उसके संबंध में हमें अपना गंभीर असंतोष व्यक्त करना चाहिए।यह न्यायिक अनुशासन के सभी सिद्धांतों के खिलाफ है।यदि न्यायाधिकरण की बाद की पीठ की राय थी कि उसी न्यायाधिकरण की समन्वय पीठ द्वारा लिया गया पूर्व दृष्टिकोण गलत था, तो उसे मामले को एक बड़ी पीठ को भेजना चाहिए था ताकि एक ही मुद्दे पर दोनों समन्वय पीठों के बीच मतभेद से बचा जा सके। ऐसा नहीं है कि बाद की पीठ पहले की पीठ के फैसले से अनजान थी, लेकिन जानबूझकर वह सभी ज्ञात नियमों के खिलाफ उक्त फैसले से असहमत हो गई। कानून के नियमों को प्रतिपादित करने वाले उदाहरण हमारी प्रणाली के तहत न्याय प्रशासन की नींव बनाते हैं। यह एक मौलिक सिद्धांत है जिसे न्यायिक मंच के प्रत्येक पीठासीन अधिकारी को जानना चाहिए, क्योंकि केवल कानून की व्याख्या में निरंतरता से ही हमारी*

न्यायिक प्रणाली में जनता का विश्वास बढ़ सकता है।इस न्यायालय ने बार-बार यह निर्धारित किया है कि पूर्ववर्ती कानून का पालन सभी संबंधित लोगों द्वारा किया जाना चाहिए; इससे विचलन केवल कानून को ज्ञात प्रक्रिया पर होना चाहिए।एक अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालयों द्वारा बनाए गए कानून के उच्चारण से बंधा होता है।न्यायालय की एक समन्वित पीठ किसी अन्य पीठ द्वारा की गई कानून की घोषणा के विपरीत निर्णय नहीं दे सकती है।यह केवल तभी इसे एक बड़ी पीठ के पास भेज सकता है जब वह पहले की घोषणा से असहमत हो।त्रिभुवनदास पुरुषोतमदास ठक्कर बनाम रतीलाल मोतीलाल पटेल [आल इंडिया रिपोर्टर 1968 सर्वोच्च न्यायालय 372:(1968) 1सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट 455] एक ऐसे मामले पर विचार करते हुए जिसमें उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश उसी न्यायालय की एक बड़ी पीठ के पहले के फैसले का पालन करने में विफल रहा था, इस प्रकार टिप्पणी कीः

> "गुजरात उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ का निर्णय राजू, जे. पर बाध्यकारी था, यदि विद्वान न्यायाधीश का विचार था कि भगवती, जे., का निर्णय पिंजरे करिंभाई मामले में [पिंजरे करिंभाई बनाम शुक्ला हरिप्रसाद, (1962) 3 गुजरात एल. आर. 529] और मैकलियोड, सी. जे., हरिदास मामले में [हरिदास बनाम रतनसे, ऑल इंडिया रिपोर्टर 1922 बम 149 (2):23 बॉम एल. आर. 802] ने सही कानून या व्यवहार के नियम को निर्धारित नहीं किया, यह उनके लिए खुला था कि वे मुख्य न्यायाधीश से सिफारिश करें कि इस प्रश्न पर एक बड़ी पीठ द्वारा विचार किया जाए।न्यायिक शिष्टाचार, औचित्य और अनुशासन की आवश्यकता थी कि उसे इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।न्याय के प्रशासन की हमारी प्रणाली का उद्देश्य कानून में

निश्चितता है और यह केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब न्यायाधीश समन्वय प्राधिकारी या वरिष्ठ प्राधिकारी की अदालतों के निर्णयों की अनदेखी न करें। गजेंद्रगडकर, सी. जे. ने भगवान बनाम राम चंद [ऑल इंडिया रिपोर्टर 1965 सर्वोच्च न्यायालय 1767] में कहाः

'इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि न्यायिक औचित्य और शिष्टाचार पर विचार करने के लिए यह आवश्यक है कि यदि किसी मामले की सुनवाई करने वाला कोई विद्वान एकल न्यायाधीश यह विचार रखने के लिए इच्छुक है कि उच्च न्यायालय के पहले के निर्णयों, चाहे वह खंड पीठ के हों या एकल न्यायाधीश के, पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, तो उसे एकल न्यायाधीश के रूप में बैठकर उस जांच को शुरू नहीं करना चाहिए, बल्कि मामले को खंडपीठ को भेजना चाहिए, या किसी उचित मामले में, संबंधित कागजात मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखना चाहिए ताकि वह प्रश्न की जांच करने के लिए एक बड़ी पीठ का गठन कर सके।ऐसे मामलों से निपटने का यह उचित और पारंपरिक तरीका है और यह यह न्यायिक शिष्टाचार और औचित्य के स्वस्थ सिद्धांतों पर आधारित है।"

6.10. उपर्युक्त मामले में, संबंधित न्यायाधिकरण न्यायाधिकरण की समन्वय पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से अवगत था, जिसके बावजूद, न्यायाधिकरण की बाद की पीठ ने माना कि न्यायाधिकरण की समन्वय पीठ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण गलत था।इसलिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि न्यायाधिकरण की बाद की पीठ को मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेजना चाहिए था ताकि एक ही मुद्दे पर दोनों समन्वय पीठों के बीच मतभेद से बचा जा सके।माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि किसी न्यायालय की

समन्वय पीठ किसी अन्य पीठ द्वारा की गई कानून की घोषणा के विपरीत निर्णय नहीं दे सकती है।यह केवल एक बड़ी पीठ को संदर्भित कर सकता है, यदि वह पहले की घोषणा से असहमत हो।

6.11. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए उपर्युक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, यदि वर्तमान मामले के तथ्यों की जांच की जाती है, जैसा कि यहां ऊपर चर्चा की गई है, तो यह कहा जा सकता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश के लिए किसी अन्य विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से भिन्न होना खुला था। हालाँकि, उस मामले में, विद्वान एकल न्यायाधीश के लिए एकमात्र विकल्प यह था कि उसे एक बड़ी पीठ को भेजा जाए और द्वारा याचिका का निपटारा नहीं किया जाए। एक विपरीत दृष्टिकोण लेना।वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर देखा गया है, विद्वान एकल न्यायाधीश 2020 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 7056 में एक अन्य विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए विचार से सहमत नहीं थे। इसलिए, उचित मार्ग यह था कि मामले को बड़ी पीठ को भेजा जाए।इसके अलावा, विद्वान एकल न्यायाधीश ने पहले ही याचिका को गुण-दोष के आधार पर यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि वह समन्वय पीठ के फैसले से अलग है और याचिका को खारिज करने के बाद, कानून का प्रश्न विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा तैयार किया गया था, जिसे संदर्भित किया गया है।जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, न्यायिक औचित्य और शिष्टाचार की अपेक्षा है कि यदि किसी मामले की सुनवाई करने वाला कोई विद्वान एकल न्यायाधीश समन्वय पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण लेने के लिए इच्छुक है, तो उसे मामले को खंड पीठ/बड़ी पीठ को भेजना चाहिए।

6.12. इस स्तर पर, हम पटना में उच्च न्यायालय के नियमों के अध्याय-V के नियम 1 का भी उल्लेख करना चाहेंगे।यह एक पूर्ण पीठ के संदर्भ का प्रावधान करता है।अध्याय 5 के नियम 1 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैंः.

अध्याय 5- *एक पूर्ण पीठ का संदर्भ-*

1. जब भी कोई खंड पीठ चाहे और मुख्य न्यायाधीश इस बात पर सहमति दे कि किसी भी मामले को पूर्ण पीठ को भेजा जाएगा, या जब भी किसी भी मामले में 2023 (7) की पटना उच्च न्यायालय की खंड पीठ सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला को भेजा जाएगा। कानून के बल वाले कानून या उपयोग के किसी बिंदु पर किसी अन्य खंड पीठ से अलग, ऐसा मामला पूर्ण पीठ द्वारा निर्णय के लिए भेजा जाएगा।"

6.13. पटना में उच्च न्यायालय के नियमों में निहित उपर्युक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट होता है कि जब भी कोई खंड पीठ चाहेगी और माननीय मुख्य न्यायाधीश इस बात पर सहमति देंगे कि किसी मामले को पूर्ण पीठ को भेजा जाएगा, तो ऐसे मामले को पूर्ण पीठ द्वारा निर्णय के लिए भेजा जाएगा।इसके अलावा, जब भी किसी मामले में एक खंड पीठ किसी अन्य खंड पीठ से कानून के बल वाले कानून या उपयोग के मुद्दे पर अलग होती है, तो ऐसे मामले को पूर्ण पीठ द्वारा निर्णय के लिए भेजा जाएगा।

6.14. इस प्रकार, दो परिस्थितियों में, एक खंड पीठ किसी मामले को पूर्ण पीठ को भेज सकती है।सबसे पहले, पूरे मामले को संदर्भित किया जा सकता है।तथापि, इसके लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश की सहमति आवश्यक है।दूसरा, यदि कोई खंड पीठ किसी अन्य डिवीजन बेंच से अलग है, तो कानून के बल वाले कानून या उपयोग के मुद्दे पर, ऐसे मामले को पूर्ण बेंच द्वारा निर्णय के लिए भेजा जाएगा।

6.15. वर्तमान मामले में, हम उपर्युक्त नियम के दूसरे भाग से संबंधित हैं। उपर्युक्त नियम के दूसरे भाग से, यह स्पष्ट है कि यदि एक खंड पीठ किसी कानूनी बिन्दु या कानून की शक्ति रखने वाले प्रचलन पर   अन्य खंड द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण रखना चाहती है, तो उस मामले को पूर्ण खण्ड पीठ के समक्ष संदर्भित करना आवश्यक है।

नियम में " शैल" शब्द का प्रयोग किया गया है।अ अतः हमारा मत है कि यदि खढण्ड पीठ किसी कानूनी बिन्दु पर अन्य खण्ड पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से भिन्न दृष्टिकोण अपनाना चाहती है, तो उस मामले को पूर्ण पीठ के समक्ष संदर्भित करना अनिवार्य है।

6.16. हमारा विचार है कि यदि उक्त सादृश्य एक विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध मामले पर लागू होता है, तो विद्वान एकल न्यायाधीश को कानून के मुद्दे को बड़ी पीठ को संदर्भित करने की आवश्यकता होती है, यदि विद्वान एकल न्यायाधीश कानून के प्रश्न पर किसी अन्य विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण लेना चाहता है।

6.17. वर्तमान मामले में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने पहले ही समन्वय पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण अपनाकर याचिका को खारिज कर दिया है और उसके बाद इस मुद्दे को बड़ी पीठ को भेज दिया है, जो विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपनाया गया सही तरीका नहीं है।इसके अलावा, अब निर्दिष्ट मुद्दे का निर्णय केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है जब याचिका को ही विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पहले ही खारिज कर दिया गया हो।

निष्कर्ष:

7. उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम विचार है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिया गया संदर्भ गलत है और मान्य नहीं है और इसलिए, वर्तमान याचिका में, याचिका को खारिज करने के बाद इसका निर्णय नहीं लिया जा सकता है।

7.2. यह स्पष्ट किया जाता है कि हमने मामले के गुण-दोष की जांच नहीं की है। इसलिए, याचिकाकर्ता के लिए उपयुक्त मंच के समक्ष उचित कार्यवाही दायर करके विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय को चुनौती देने के लिए हमेशा खुला है।

7.3. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, हम कार्यालय को वर्तमान आदेश के साथ मामले को माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश देते हैं।

(विपुल एम. पंचोली, न्यायमूर्ति)

(आलोक कुमार पांडे, न्यायमूर्ति)

पवन-आलोक

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।